

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून

दिनांक 2 जुलाई, 2014

विषय: कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अल्मोडा परिसर में ऑडिटोरियम भवन की साज-सज्जा से संबंधित कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: केयू/भवन/254/2014/190 दिनांक: 15.3.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अल्मोडा परिसर में ऑडिटोरियम की साज-सज्जा से संबंधित कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुमाऊ विश्वविद्यालय के अल्मोडा परिसर में ऑडिटोरियम भवन की साज-सज्जा के कार्यों हेतु उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा गठित आंगणन ₹ 143.33 लाख के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत धनराशि ₹31.77 लाख की शासनादेश संख्या: 10/XXIV(6) 2011 दिनांक: 8.9.2011 द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्गत की गई थी। इस संबंध में टी०ए०सी० द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ऑडिटोरियम भवन की साज-सज्जा से संबंधित अन्य अवशेष कार्यों हेतु वर्तमान में अनुमोदित धनराशि ₹ 90,62,000/—(₹ नब्बे लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- कुलपति, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कर लिया गया है। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी०एल०ए० में रखी जायेगी एवं दायित्व उत्पन्न होने पर ही चरणबद्ध रूप से कार्यदायी संस्था की आवश्यकतानुसार ही धनराशि अवमुक्त की जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल से प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक धनराशि रोककर कार्य की लागत में वृद्धि नहीं की जाएगी।
- उक्त स्वीकृत धनराशि में **Uttarahand Procurement Rules, 2008** के अनुसार कराए जाने वाले कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु उक्त अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब अन्तिम किस्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम

किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

- v. आंगणन दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट के स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य के आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- vi. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- vii. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण सामग्री उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाय।
- viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- ix. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 2047/XIV-2219(2006) दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

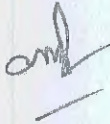
3- निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जाएगी।

4- व्यय उन्हीं कार्यों/योजनाओं मर्दों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक: 18.3.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार एवं पूर्व में निर्गत वित्तीय मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय, भौतिक विवरण आदि की सूचना प्रशासकीय विभाग के साथ ही नियोजन/वित्त विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा कार्यों की सतत मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

7- निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)2007 दिनांक 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रकरणाधीन कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक: 551/XXVII(1)2010 दिनांक: 19.10.2010 के आलोक में द्वितीय चरण के प्राथमिक कार्यों के लिए समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।



8- उक्त कार्यो हेतु विगत शासनादेश संख्या: 10/XXIV(6)2011 दिनांक: 8.9.2011 में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

9- उक्त संबंध में साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या- द्वारा निर्गत पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-14-कुमाऊ विश्वविद्यालय-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 994 (1)/XXIV(6)/2014/2(4)12 दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, अल्मोडा।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

उप सचिव।

